मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मंत्रियों व विधायकों के साथ रामलला के दर्शन किए

अयोध्या/जयपुर, 11 मार्च (का.सं.)। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को अपने मंत्रिपरिषद् के सदस्यों और विधायकों के साथ अयोध्या पहुंचे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह उनकी पहली अयोध्या यात्रा थी। मुख्यमंत्री ने अयोध्या के श्रीराम मंदिर में रामलला के दर्शन किए और पूजा अर्चना कर देश- प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राम हमारी आस्था के केन्द्र हैं, पहले अयोध्या में टैंट में विराजमान रामलला के दर्शन किए थे, अब इस भव्य और दिव्य मंदिर में भगवान के दर्शन करना अभिभूत करने वाला है। रामलला के दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री ने मंत्रियों, विधायकों, अधिकारियों एवं अन्य सहयोगियों के साथ जय श्रीराम का उद्घोष करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शर्मा ने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ तस्वीरें खिंचवाई और राम मंदिर निर्माण कार्य सें जुड़े श्रमिकों और कारीगरों से भी बात की।

अयोध्या पहुंचते ही, मुख्यमंत्री शर्मा दशरथ कुंड में अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन पुष्कर की ओर से आयोजित सरस्वती देवी शिव किशन दम्मानी भवन के भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और मुख्यमंत्री ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन की पूर्णाहुति में हिस्सा लिया।

मुख्यमंत्री ने कहा, रामभक्त के तौर पर उन्हें भी राम जन्मभूमि आंदोलन में योगदान देने का अवसर मिला था। उन्होंने आंदोलन के अनुभव भी साझा किए। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में अध्यात्म और सांस्कृतिक क्षेत्र के विकास कार्यों को समर्पण के साथ पूरा करवा रहे हैं।

मुख्यमंत्री शर्मा ने राज्य सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा 3,000 वरिष्ठ तीर्थयात्रियों को अयोध्या की यात्रा करवाई जा रही है। जयपुर से अयोध्या के लिए विशेष विमान सेवा शुरू की गई है। राजस्थान के सात संभाग मुख्यालयों से श्री रामलला के दर्शन हेतु राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें चलाई हैं।

मुख्यमंत्री ने माहेश्वरी समाज की परोपकार भावना की सराहना करते हुए कहा कि यह समाज सदैव ही मानव कल्याण की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि माहेश्वरी समाज की ओर से अयोध्या में बनने जा रहा यह भवन श्रद्धालुओं को उत्तम सेवाएं प्रदान करेगा।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविन्दगिरि महाराज ने मुख्यमंत्री शर्मा और उनके मंत्रिपरिषदीय सदस्यों के अयोध्या आगमन को सुखद बताते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे पूरा राजस्थान ही राम की पूजा करने आया है। स्वामी श्रीधराचार्य ने भी कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए इस सामाजिक कार्य की पहल की सराहना की। अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन पुष्कर के अध्यक्ष रामकुमार भूतड़ा ने दशरथ कुण्ड में बनने जा रहे भवन और माहेश्वरी समाज की ओर से संचालित सेवा कार्यों एवं सामाजिक कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने भूमि के लिए दान देने वाले भामाशाह और प्रसिद्ध उद्यमी राधाकृष्ण दम्मानी का आभार भी प्रकट किया। इस दौरान विधानसभाध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, उत्तर प्रदेश विधानसभाध्यक्ष सतीश महाना, केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, राजस्थान सरकार के मंत्री, सांसद सी.पी. जोशी, सांसदगण, विधायकगण, मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित वरिष्ठ अधिकारीगण, समाजसेवी एवं गणमान्यजन उपस्थित थे।

अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को अपने मंत्रिपरिषद् के सदस्यों और विधायकों के साथ वापस जयपुर लौटे तो समर्थकों ने उनका एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया।

- रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार अयोध्या गए मु.मंत्री शर्मा।
- दर्शन कर भावुक हुए मुख्यमंत्री शर्मा बोले, पहले टैंट में देखा था, अब भव्य मंदिर में दर्शन कर अभिभूत हैं।
- मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव सुधांश पंत, उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा और केन्द्रीय मंत्री कैलाश चौधरी भी थे।

सी.ए.ए. के क्रियान्वयन पर सवाल उठाया कांग्रेस ने

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 मार्च। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने चुनाव से पहले सिटीज़न शिप अमेंडमैंट एक्ट के नियम जारी करने के लिए मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की और कहा कि यह कदम चुनावों में खासकर पश्चिम बंगाल ओर असम के चुनावों में मतों के ध्रुवीकरण के लिए उठाया गया है।

उन्होंने कहा कि ऐसा भी लगता है कि चुनावी बॉण्ड पर एस.बी.आई. पर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मिल रही सुर्खियों को मैनेज करने के लिए भी यह कदम उठाया गया है।

- कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि, एक्ट 2019 में पारित हुआ था, तब से सरकार नियम बनाने के लिए बार-बार टाइम बढ़ाती रही और वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए चुनाव से पहले कानून का क्रियान्वयन किया गया है।

उन्होंने कहा कि 2019 में बिल पारित होने के बाद सरकार को नियम अधिसूचित करने में 4 साल 3 महीने लग गए।

जयराम ने कहा कि प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि उनकी सरकार बिज़नैस की तरह और नियमित समयावधि में काम करती है। लेकिन सी.ए.ए. के नियमों को अधिसूचित करने में जो समय लगा उससे स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते है। उन्होंने बताया कि चुनाव से ठीक पहले नियम जारी करने के लिए नियम तैयार करने की अवधि नौ बार बढ़ाई गई।

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

सुप्रीम कोर्ट याचिका को तत्काल विचार हेतु सूचीबद्ध करने के लिए सहमत हुआ

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 मार्च। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि, वह 2023 में पारित कानून के अनुसार केन्द्र सरकार को नये चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने से रोकने वाली याचिका जल्दी सुनवाई करने के लिए सूचीबद्ध कराने पर विचार करेगा, क्योंकि 2023 में बने कानून को पहले ही शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।

- मध्य प्रदेश की कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने यह याचिका दायर की थी। उनके वकील एडवोकेट विकास सिंह और वरूण ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका पर शीघ्र विचार करने का अनुरोध किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है।

देश के चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों के दो पद रिक्त हुए हैं, एक पद चुनाव आयुक्त अरूण गोयल के द्वारा पद से इस्तीफा देने के कारण व दूसरा अनुप चन्द्र पाण्डेय की सेवानिवृति होने से। मामले की सुनवाई तत्काल व सूचीबद्ध करने के लिए कांग्रेसी नेता जया ठाकुर की ओर से कोर्ट में पैरवी के लिए उपस्थित वरिष्ठ वकील विकास सिंह व वकील वरूण ठाकुर ने अनुरोध किया। स्थानीय कांग्रेस नेता ने मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों की (नियुक्ति, सेवा की शर्ते व पदों के कार्यकाल) अधिनियम, 2023 के प्रावधानों को कोर्ट में चुनौती दी है।

कांग्रेसी नेता ठाकुर ने अपने आवेदन में कोर्ट को सूचित किया कि उनकी याचिका के लम्बित रहने के दौरान, 12 जनवरी को एक नोटिस जारी किया था "चुनाव आयोग के एक सदस्य जिनका नाम अरूण गोयल है, ने 9 मार्च 2024 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार भी कर लिया है।"

याचिका में कहा गया है कि "याचिकाकर्ता ने विनम्रतापूर्ण निवेदन किया कि लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावों की घोषणा शीघ्र ही होने वाली है, इस तथ्य के मद्देनजर, नये चुनाव आयुक्तों के सदस्यों की नियुक्ति तुरंत किए जाने की जरूरत है, इसके लिए यह न्यायालय नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में "अनूप बरनावाल बनाम भारत संघ (2 मार्च 2023 के फैसले में) स्पष्ट फैसला दे चुका है।"

उसने कहा कि "अत: विनम्रतपूर्वक प्रार्थना है कि यह अदालत प्रतिवादियों को यह निर्देश देने की कृपा करेगी कि वह चुनाव आयोग के सदस्य की नियुक्ति इस अदालत के द्वारा अनूप बरनाव बनाम भारत संघ के केस में पारित फैसले/निर्णय को अनुरूप करेगी।"

यदि, शीर्ष अदालत केन्द्र सरकार द्वारा दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से पहले याचिका पर विचार करने का निर्णय लेती है नियम सरकार को आगे कार्रवाई करने से रोकते हैं ऐसी स्थिति में तब देश में प्रजातंत्र के क्रियाकलापों पर बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।

सी.ए.ए. के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ए.) के नियमों को लागू करने के लिए सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी।

संसद ने यह विधेयक चार साल पहले पारित कर दिया था। सी.ए.ए. में 31 दिसम्बर 2014 के बाद या उससे पहले आए उन शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है, जिनका पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक आधार पर उत्पीड़न हुआ है। तथापि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए मुस्लिम शरणार्थियों के संबंध में यह कानून लागू नहीं है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सी.ए.ए. नियमों से संबंधित की अटकलों को लेकर कहा कि "पहले मुझे नियम देखने दीजिए। अभी तक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। यदि इन नियमों के तहत लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है तो हम उसके विरूद्ध संघर्ष करेंगे यह चुनावों के लिए भाजपा की पब्लिसिटी के अलावा कुछ नहीं है।"

कांग्रेस में शामिल हुए राहुल कस्वां

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 मार्च। राजस्थान के चूरू से भाजपा के वर्तमान सांसद राहुल कस्वा यहाँ ए.आई.सी.सी. मुख्यालय पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति में सोमवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। इससे लोकसभा चुनावों से पूर्व कांग्रेस पार्टी का मनोबल बढ़ेगा।

राहुल कस्वा के परिवार को

- लगातार दो बार चूरू से भाजपा सांसद रहे राहुल कस्वां ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की।

राजस्थान के प्रमुख राजनीतिक परिवारों में से एक माना जाता है। कस्बा चूरू लोकसभा सीट से लगातार दो बार जीत दर्ज कर चुके हैं, उनके पिता रामसिंह कस्वा यहां से चार बार सांसद रहे और उनकी मां कमला कस्वा भी यहाँ से विधायक रह चुकी हैं। उनके पिता दीपचन्द कस्वा भी मंत्री थे।

इस मौके पर, कस्वा का पार्टी में स्वागत करते हुए खड़गे ने कहा कि इससे पार्टी को राजस्थान में और मजबूती मिलेगी।

कस्वा ने कहा कि चूरू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की जनभावनाओं के आधार पर ही वह कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उन्होंने इसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का आभार व्यक्त किया।

सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की समय बढ़ाने की अर्जी खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार की शाम तक इलैक्टोरल बॉण्ड की जानकारी देने के आदेश दिये

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 मार्च। सुप्रीम कोर्ट ने देश के लोकतंत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करने को लेकर आज स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (एस.बी.आई.) की याचिका को रद्द कर दिया। कोर्ट ने बैंक को आदेश दिया कि वह इलैक्टोरल बॉण्ड्स संबंधित जानकारियां कल तक चुनाव आयोग में पेश कर दे। एस.बी.आई. की याचिका में विवादास्पद इलैक्टोरल बॉण्ड्स के विवरणों का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय मांगा गया था। शीर्ष अदालत ने सरकार द्वारा संचालित इस बैंक को यह भी चेतावनी दी कि उसने यदि कल तक जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई तो उसके खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरु की जाएगी।

चीफ जस्टिस ऑफ इण्डिया (सी.जे.आई.) डी.वाय. चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की एक बैंच ने चुनाव आयोग को यह ब्यौरा उपलब्ध करवाने के लिए एस.बी.आई. को 12 मार्च को ऑफिस ऑवर्स की समाप्ति तक का समय देते हुए चुनाव आयोग को भी निर्देश दिए हैं कि वह एस.बी.आई. से प्राप्त जानकारी को 15 मार्च की सायं 5 बजे तक अपनी वैबसाइट पर अपलोड कर दे। सी.जे.आई. चन्द्रचूड़ ने एस.बी.आई. की तरफ से पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे से कहा कि शीर्ष अदालत के निर्णय में एस.बी.आई. से इतना ही कहा गया था कि वह स्पष्ट जानकारी दे दे।

सुनवाई के दौरान बैंच ने एस.बी.आई. से कहा कि वह यह स्पष्ट करे कि राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए इलैक्टोरल बॉण्ड्स की जानकारी दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए उसने अब तक क्या-क्या कदम उठाए हैं।

साल्वे ने कहा कि विवरण तैयार करने के लिए एस.बी.आई. को थोड़ा समय और चाहिए होगा क्योंकि कोर्ट द्वारा इलैक्टोरल बॉण्ड्स स्कीम को रद्द करने से पूर्व बैंक को शुरु में बताया गया था कि यह प्रक्रिया गुप्त है।

साल्वे ने कहा कि "हम जानकारी एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं तथा इसके लिए हमें पूरी प्रक्रिया को अन्त से शुरुआत तक देखना होगा। एक बैंक के रूप में हमें यह बताया गया था कि इस काम को गोपनीय माना जाए।

सी.जे.आई. ने साल्वे से पूछा कि "कृपया बताइए आपने पिछले 26 दिन में कौन-कौन सा रिकॉर्ड मैच किया है। इस पर साल्वे ने एक विस्तृत शपथ-पत्र पेश करने का अनुरोध किया।

सी.जे.आई. को प्रकट रूप से एस.बी.आई. के पक्ष पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा कि "इस काम को लेकर एस.बी.आई. से उम्मीद की जा रही थी।"

चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की कि एस.बी.आई. के एक सीनियर अधिकारी ने संविधान बैंच के निर्णय में संशोधनों को लेकर एक शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है जो कि "एक गंभीर विषय है।"

बैंच ने ध्यान दिलाया कि प्रत्येक इलैक्टोरल बॉण्ड की खरीद पर "नो योर कस्टमर (के.वाई.सी.) प्रक्रिया की अनुपालना करनी होती थी और इस वजह से बैंक के पास इलैक्टोरल बॉण्डस के खरीदारों का विवरण पहले से ही मौजूद होगा।

मनोरंजन की दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रम "ऑस्कर अवॉर्ड्स" का सोमवार को लॉस एंजिलिस (कैलिफोर्निया) के डॉल्बी थियेटर में आयोजन हुआ। वर्ष 2024 के ऑस्कर में हॉलीवुड फिल्म "ऑपनहाइमर" का पूरी तरह से दबदबा रहा। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म "ऑपनहाइमर" ने बैस्ट फीचर फिल्म सहित कुल सात अवॉर्ड अपने नाम किये। जिसमें किलिअन मर्फी को मिला बैस्ट एक्टर और रॉबर्ट डाउनी जूनिअर को मिला सपोर्टिंग एक्टर अवॉर्ड शामिल है। "पुअर थिंग्स" के लिए एम्मा स्टोन को बैस्ट एक्ट्रैस और होल्ओवर्स के लिए ड'वाइन जॉय रैन्डॉल्फ को सपोर्टिंग एक्ट्रैस अवॉर्ड दिया गया है। क्रिस्टोफर नोलन को "ऑपनहाइमर" के लिए बैस्ट डायरेक्टर अवॉर्ड भी मिला है। चित्र में नज़र आ रहे हैं बाएं से ड'वाइन जॉय रैन्डॉल्फ, रॉबर्ट डाउनी जूनिअर, एम्मा स्टोन और किलिअन मर्फी। ऑस्कर अवॉर्ड सैरमनी कुल 4 घंटे चली तथा कुल 23 कैटिगरिज़ में अवॉर्ड दिये गये।

पायलट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राहुल कस्वा, जिन्हें भाजपा का टिकट नहीं मिला था और सोमवार को उन्होंने कांग्रेस जॉइन कर ली थी, अब कांग्रेस के टिकट पर चूरू से चुनाव लड़ेंगे।

अलवर से ललित यादव, झुंझुनूं से

- ललित यादव को कांग्रेस ने अलवर से तथा बृजेन्द्र ओला को झुंझुनूं से, चित्तौड़गढ़ से उदयलाल आंजना, झालावाड़ से प्रमोद जैन भाया, संजना जाटव को भरतपुर से व गोविंद सिंह मेघवाल को बीकानेर से टिकट देने का निर्णय लिया सी.ई.सी. की बैठक में।

बृजेन्द्र ओला, चित्तौडगढ़ से उदयलाल आंजना, झालावाड़ से प्रमोद जैन "भाया", भरतपुर से संजना जाटव तथा बीकानेर से गोविन्द राम मेघवाल चुनाव लड़ने वाले हैं। केन्द्रीय चुनाव समिति में बचे हुए उम्मीदवारों और उनके निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चर्चा जारी है।

भाजपा की दूसरी लिस्ट

नई दिल्ली, 11 मार्च। भाजपा अपने 195 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। वहीं सोमवार शाम को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दोबारा हो रही है। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पर हो रही इस बैठक में पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह समेत पार्टी के दिग्गज नेता शामिल हैं। इस बैठक में यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, केरल, गोवा और पश्चिम बंगाल की बची हुई सीटों पर चर्चा होने की संभावना है।

सी.ए.ए. का क्रियान्वयन शुरू हुआ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

होने से आगामी लोकसभा चुनावों में भाजपा को व्यावहारिक रूप से मदद मिलेगी अथवा इससे तृणमूल कांग्रेस और वामपंथियों को लाभ होगा।

सी.ए.ए. के प्रवर्तन से करीब 71 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को निश्चित रूप से मदद मिलेगी जहां पहले के पूर्वी बंगाल से विस्थापित नामाशूद्र या मोतुआ वोटर्स के पास जीत का इक्का है। इसके अलावा अन्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में रह रही शरणार्थी आबादी से भाजपा को सकारात्मक मदद मिलेगी।

दूसरी तरफ, पश्चिम बंगाल की अल्पसंख्यक आबादी इसके कारण भाजपा के खिलाफ लामबंद हो सकती है।

पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए लोगों के लिए मद्दगार ऐसी कार्रवाई के क्रियान्वयन का विरोध करना जहां कठिन है, वहीं भाजपा के राजनीतिक विरोधी इस कानून को लागू करने के समय विशेष को लेकर अब प्रश्न खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी क्यों? अगले चुनाव के ठीक पहले क्यों?

सी.ए.ए. के पक्ष और विपक्ष के राजनीतिक धड़े चुनाव पर चुनाव, एक लम्बे समय से इस मुद्दे पर एक दूसरे की आलोचना कर रहे थे। इसके विरोधी अब इन कानूनों को लागू नहीं करने की मांग कर रही हैं।

वर्ष 1947 में जब विभाजन की रेखा खीचीं गई थी तब पहले के पूर्वी पाकिस्तान में फंसे लोगों की नागरिकता का मुद्दा अनिश्चित था, हालांकि राष्ट्रवादी नेताओं ने इन लोगों को भारत में एक स्थायी जगह का आश्वासन दिया था।

आज भी करीब 20 से 25 करोड़ बंगाली, जिनके पूर्वज पूर्वी पाकिस्तान से आए थे, पासपोर्ट या अन्य के लिए आवेदन करने के दौरान दस्तावेज़ों की समस्या का सामना करते हैं। पुलिस वैरिफिकेशन के दौरान उनसे वर्ष 1971 के पूर्व के अपने कागजात दिखाने के लिए कहा जाता था।

अब नए नागरिकता अधिनियम के अन्तर्गत इन जरूरतों का खत्म कर दिया गया है। वर्ष 1947 में बंगाल के कई अग्रणी राजनेताओं ने जवाहरलाल नेहरू से अनुरोध किया था कि अविभाजित बंगाल के हिंदू बाहुल्य जिलों को भारत में शामिल कर लिया जाए, लेकिन उदाहरण के तौर पर खुलना और जैसोर जैसे क्षेत्रों को भारत में नही मिलाया गया जो एक तरह से उनके साथ विश्वासघात था।

इसके बाद, वादों के बावजूद कई वर्षों तक स्थायी नागरिकता नहीं दी गई, लेकिन आखिरकार अब इस वादे को पूरा कर दिया गया है।

इंडिपैंडेन्ट टारगैट मिसाइल अग्नि-5 का परीक्षण सफल

नई दिल्ली, 11 मार्च (वार्ता)। डिफैन्स रिसर्च एंड डवलपमैंट रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (डी.आर.डी.ओ.) ने सोमवार को देश में ही विकसित अग्नि-5 मिसाइल, मिशन दिव्यास्त्र का पहला सफल परीक्षण किया।

इसके साथ ही भारत 'मल्टीपल इंडिपैंडेन्टली टारगैटेबल री-एंट्री व्हीकल' (एमआईआरवी) तकनीक पर आधारित मिसाइल विकसित करने वाले दुनिया के चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए वैज्ञानिकों को बधाई दी है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी विशेषता है कि, यह एक साथ अनेक स्थानों पर मुखास्त्र का इस्तेमाल कर सकती है।

सरकारी सूत्रों ने बताया कि, इस परियोजना में नारी शक्ति की बड़ी भूमिका है क्योंकि इसकी निदेशक एक महिला वैज्ञानिक है। यह प्रणाली स्वदेशी एवियोनिक्स प्रणालियों और उच्च क्षमता वाले सटीक सेंसर पैकेजों से सुसज्जित है। यह क्षमता भारत की बढ़ती तकनीकी शक्ति का प्रतीक है।

प्र.मंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अग्नि - 5 मिसाइल के पहले सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वैज्ञानिकों पर गर्व है। राजनाथ सिंह ने भी कहा कि देश को इस असाधारण उपलब्धि के लिए वैज्ञानिकों पर गर्व है।

मायावती किस करवट बैठेंगी चुनाव में?

हालांकि मायावती सार्वजनिक रूप से कह चुकी हैं कि, उनकी पार्टी अगला चुनाव "अकेले" ही लड़ेंगी, पर, उनकी बात पर विश्वास कम है लोगों को

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 मार्च। बसपा अध्यक्ष मायावती का यह बयान कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव स्वतंत्र रूप से अकेले लड़ेगी, इसके बाद भी इन कयासों पर विराम नहीं लगा है कि वे लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के बाद भी अंतिम क्षणों में इंडिया ब्लॉक में शामिल हो सकती हैं।

इस तरह की खबरों के जायज कारण हैं। मायावती पार्टी ने 2022 में सम्पन्न उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव अकेले स्वतंत्र लड़ा था और उनकी पार्टी को चुनावों में करारी पराजय मिली थी। लोकसभा चुनावों में भी पार्टी की वैसी ही बुरी हालत हो सकती है यदि वे अपनी "एकला चालो" की रणनीति पर अडिग सरकार अमल करती है तो। इस लिहाज से, आगामी चुनाव उनके लिए अंतिम विकल्प के रूप में हो सकता है कि वो संभावित राजनीतिक पुनर्जीवन चुने या पूर्णरूप से निरर्थक बन जाए।

जैसा कि खबरों से ज्ञात होता है कि, कांग्रेस ने चुनावों को लेकर मायावती को लुभाने वाले पैकेज प्रस्ताव दिया है: उन्हें इंडिया ब्लॉक की तरफ से प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित किया जाएगा, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में लगभग 27 लोकसभा की सीटें उनकी पार्टी के लिए आवंटित की जाएंगी। चल रही खबरों के अनुसार, इस मामले पर सोनिया गांधी व मायावती के बीच प्रारंभिक स्तर की वार्ता हो चुकी है, जबकि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के भी इस तरह की बैठक में मौजूद रहने की बात कही जा रही है, ऐसी भी खबरें है कि हाल ही में, दिल्ली में समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल व बसपा नेता सतीश मिश्रा के बीच इस मामले में मुलाकात हुई है।

- चर्चा तो यह है कि, चुनाव के अंतिम क्षणों में, वे इण्डिया गठबंधन से जुड़ जायेंगी।
- कांग्रेस ने बहुत आकर्षक पैकेज दिया है मायावती को, जिसके अनुसार इण्डिया गठबंधन उन्हें अपने प्र.मंत्री के उम्मीदवार के रूप में प्रोजैक्ट करेगा, साथ ही गठबंधन उन्हें 27 लोकसभा सीटें भी देने को राजी है यू.पी. में।
- सोनिया गांधी व मायावती के बीच इस बारे में बातचीत भी हो चुकी है तथा इण्डिया गठबंधन के इस ऑफर पर अखिलेश यादव को भी आपत्ति नहीं है।
- पर, दूसरी ओर यह भी चर्चा है कि, मायावती की भाजपा से भी बातचीत चल रही है तथा मायावती भाजपा से और बेहतर ऑफर आने का इंतज़ार कर रही हैं।

ऐसे भी संकेत हैं कि विभिन्न कारणों के चलते उत्तर प्रदेश में कुछ न कुछ खिचड़ी अवश्य पक रही है। पहला कारण उनकी सुस्थापित कार्य शैली के विरूद्ध अखिलेश यादव ने अपनी कोई विपरीत प्रक्रिया व्यक्त नहीं की है। तीसरा-मायावती की राजनैतिक हैसियत आज सबसे निचले स्तर पर दिख रही है, वे चार बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और उनके ऐसे दिन चल रहे हैं कि उन पर ऐसे आरोप लग रहे हैं कि वे भाजपा की बी टीम के रूप में कार्य कर रही है।

यह भी संभव है कि मायावती अभी अपना दाव टाल रही है और भाजपा की तरफ से अच्छा प्रस्ताव आने की प्रतीक्षा कर रही हों। किसी भी स्थिति में, यदि वे भाजपा के साथ समझौता करती हैं तो यह एक अनौपचारिक स्तर का होगा। ऐसी स्थिति में मायावती भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बन सकती हैं, जो वे एक से अधिक बार बन चुकी है, परन्तु उन्होंने भगवा पार्टी के साथ गठबंधन करके कभी चुनाव नहीं लड़े हैं। वर्तमान में, सबकी निगाहें मायावती पर है।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908